2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
-	1	1	-	1

The Details of the above has been furnished below

S.N.	Name of the teacher	Title of the book published	Title of the Chapter	National/ International	Year of publication	ISBN/ISSN Number of the proceeding	Name of the publisher
1	Minakshi Thakur	Dalit Adivasi Human Rights	मानव अधिकार और दलित आदिवासी महिलाएं	National	2017	978-93-84198-99-2	BSPK Book Publishing Company

2	Minakshi Thakur	विकास और आदिवासी	अबूझमाडिया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था में आर्थिक विकास व भूमंडलीकरण का प्रभाव (छत्तीसगढ़ राज्य के जिला - नारायणपुर के विशेष संदर्भ में	National	2019	978-93-84686-87-1	Institute for social development and research
3	Minakshi Thakur	Depletion of Water	जल वर्तमान की प्रमुख आवश्यकता	National	2021	978-81-952235-4-1	Institute for social development and research

Supporting Photo:

First page of books published form our faculty in the last five years 2016-2017 to 2020-2021.

2017-2018 Entry No. (1)

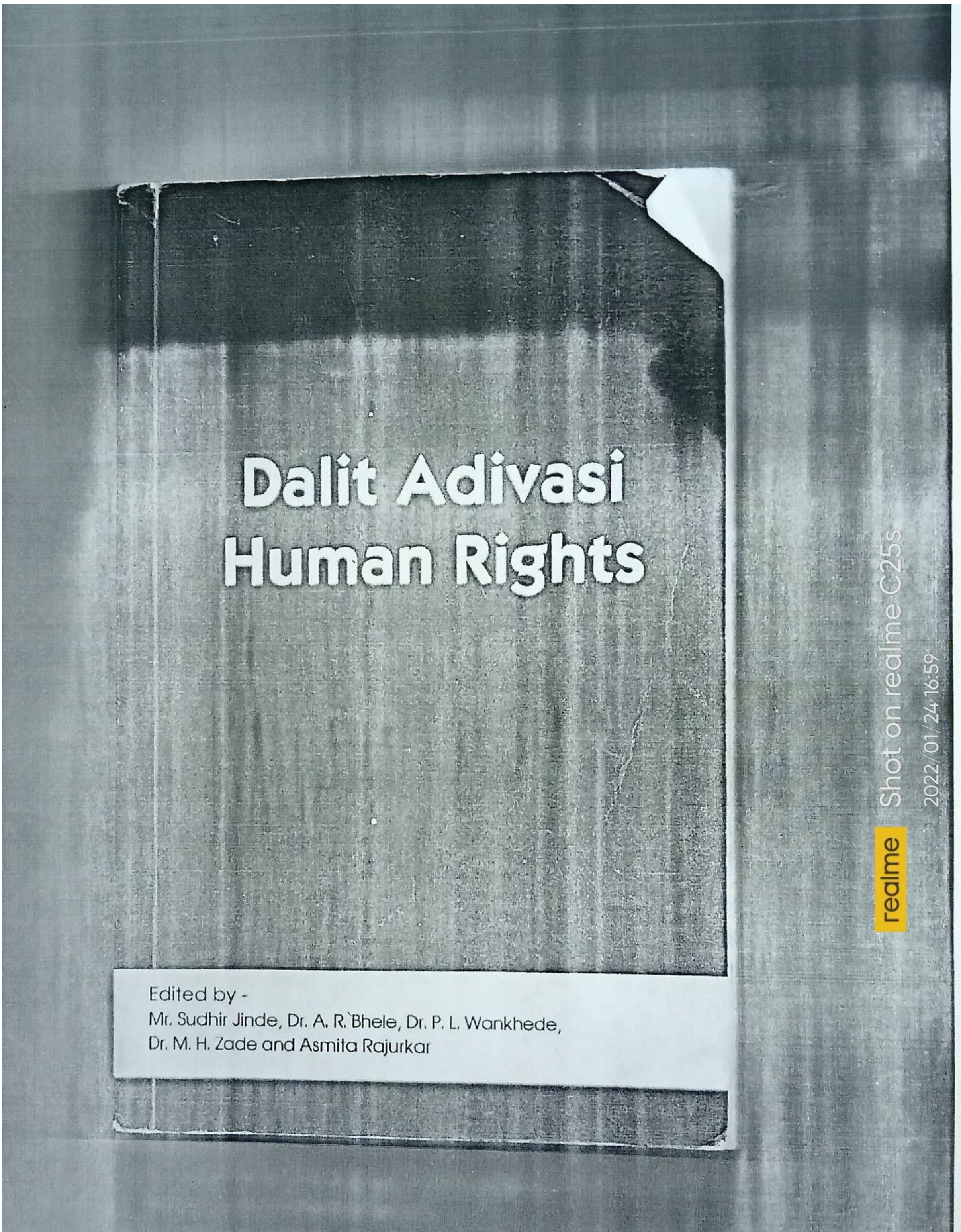
Dalit Adivasi
Human Rights
Edited by -
Mr. Sudhir Jinde, Dr. A. R. Bhele, Dr. P. L. Wankhede,
Dr. M. H. Zade and Asmita Rajurkar
realme Shot on realme C25s
2022/01/24 16:59

मानवाधिकार और दलित आदिवासी महिलाएँ

■ श्रीमती मीनाक्षी ठाकुर
शोद्यार्थी, बस्तर विश्व विद्यालय जगदलपुर (छ.ग.)

हमारे देश ने आज वैश्विक स्तर को प्राप्त कर लिया हैं। आईटी, न्यूक्लीयर एनर्जी के उत्पादन, संचार और अंतरिक्ष तकनीक आदि क्षेत्रो में भारत विश्वस्तरीय स्पर्धाओं में आगे बढ रहा हैं और इन्ही क्षेत्रो में भारतीय महिलाएँ भी आगे बढ रही हैं। बिजनेस, मार्केट, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर और स्पोर्टस आदि विश्वस्तरीय प्रोफेशन में महिलाएँ नाम कमा रही हैं। कई महिलाएँ प्रोफेशर टीचर्स जैसे बौधिक क्षेत्रो के लिए विदेशो में अतिथि व्याख्यानो के लिए बुलाई जा रही हैं ,लेकिन इन सभी का अभी बहुत कम प्रतिशत हैं। हम विशेष रूप से दलित और आदिवासी महिलाओं की बात करे तो आज भी वे अज्ञानता से जूझ रही है। वे अधिकार हीन है। और इनकी बातो का ध्यान नही दिया जाता हैं। वे भयग्रस्त होती हैं और अपने अधिकारों के प्रति-आवाज नहीं उठा पाती है स्वतंत्रता के समय-से देश के संविधान के सकारात्मक सिद्वांतो के आधार पर कानून की नजर में सभी महिलाएँ समान है। सभी महिलाओ के लिए सुरक्षा समान हैं। संविधान के अनुसार जातीयता लिंग, धर्म आदि पर कोई भेदभाव नही किया जाएगा ।

वर्तमान आधुनिकयुग जिसे तृतीय-विश्व भी कहा जा रहा है।, इसकी चकाचौंध में मानव लुप्त-सा होते जा रहा है और मानवाधिकारों का प्रश्न एक नई चुनौती बनकर हमारे सामने खडा है। मानवाधिकार वे अधिकार है जो हमारी प्रकृति, स्वभाव या व्यक्तित्व विकास के साथ जुडे हुए है मनुष्य को अपने सप्त गुणो एवं क्षमताओं के विकास के लिए कुछ अधिकारो की आवश्यकता होती है, क्योकि इन्ही अधिकारों से स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति होती है। और स्वतंत्र वातावरण में मनुष्य के व्यक्गित गुणों का विकास संभव होता है। मानवाधिकारों का सीधा सम्बन्ध मानवीय सुखो से है और सुख की अवधारणा को तभी से श्रेयस्कर मानना होगा जब से मानव जाति, समाज एवं राज्य का उदय हुआ है जब से राज्य में समाज व्यवस्था व जाति व्यवस्था के सूत्रपात के बाद दलित एवं आदिवासी वर्ग के साथ मानवीय अधिकारों का हनन होता आया है। समाज में कई स्तर पर कई तरह के विभेद पाए जाते है। भाषा, एवं मानसिक स्तर प्रजातीय स्तर आदि इन स्तरो पर मानव समाज में भेदभाव का बर्ताव किया जाता है। स्त्री पुरूष के आधार पर भी भेदभाव का स्तर मौजूद है। मानव जब दानव बनकर मानव पर अत्याचार करता है तो मानवाधिकार का हनन होता है मानवाधिकार हेतु अनेक

2019-2020 Entry No. (1)

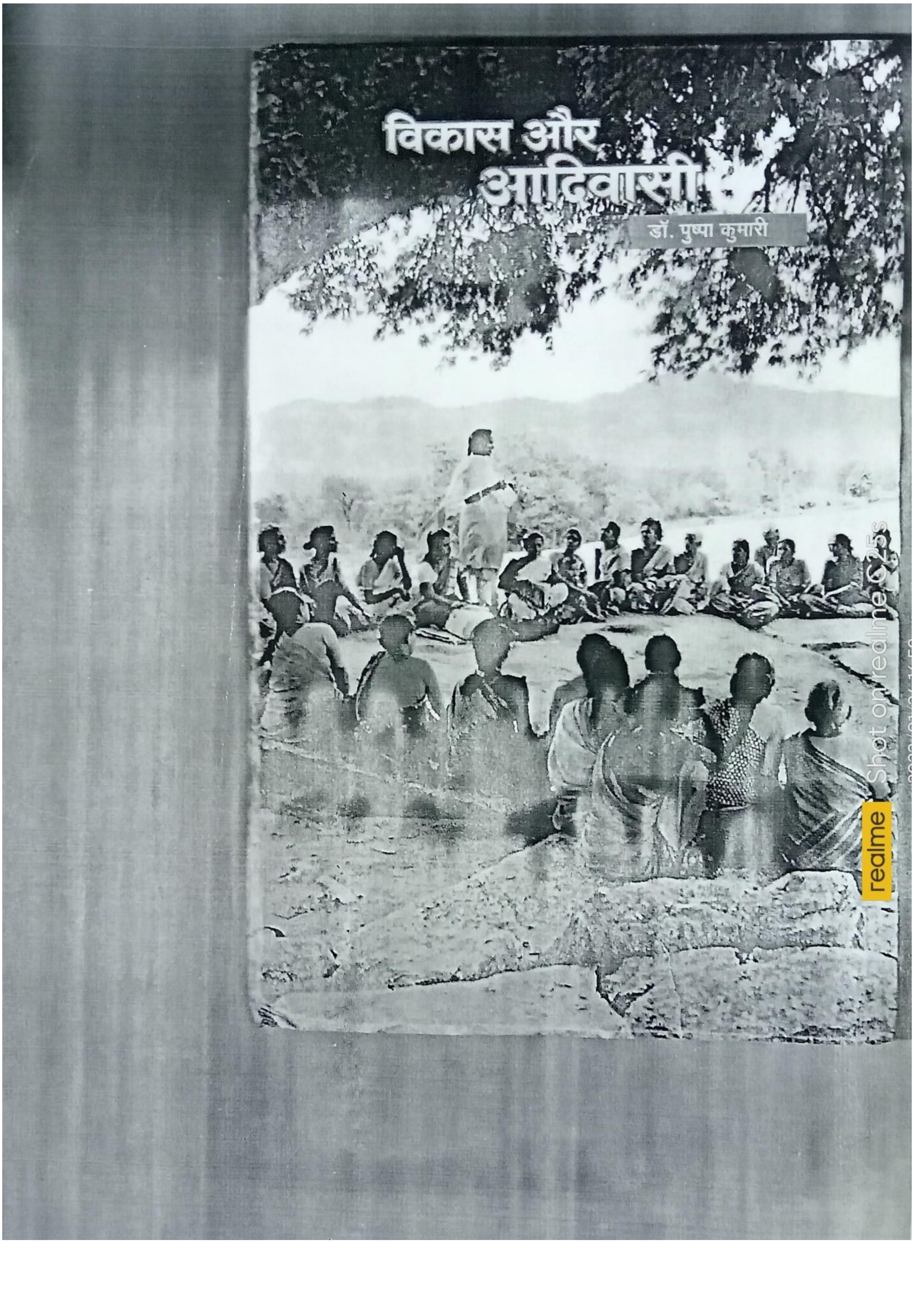

अबुझमाड़िया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था में आर्थिक विकास व भूमण्डलीकरण का प्रभाव (छत्तीसगढ़ राज्य के जिला- नारायणपुर के विशेष सन्दर्भ में)

मीनाक्षी ठाकुर
शोधार्थी (राजनीति विज्ञान), बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर, छत्तीसगढ़
सम्प्रति- अतिथि व्याख्याता, राजनीति विज्ञान विभाग,
शासकीय स्वामी आत्मानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नारायणपुर, छत्तीसगढ़.

अध्ययन पद्धति

सोने की चिड़िया कभी सांप और संपेरो का देश कहलाने वाला भारत भूमण्डलीकरण के वर्तमान दौर में विश्व का सबसे तेजी से प्रगति करता मुक्त बाजार वाला लोकतंत्र परिभाषित किया जाने लगा है। भारत की सांस्कृतिक समरसता लोकतांत्रिक सत्यता एवं तर्कशील जीवंतता में आर्थिक समृद्धि का एक नया अध्याय जुड़ गया है। इसके फलस्वरूप भारत एक राष्ट्र नहीं अपितु एक आशा, अवसर, आकांक्षा और विश्वास का वैश्विक प्रतीत बनकर उभरा है।

प्रस्तुत शोधपत्र गतिशील एशियाई आर्थिक विकास के भूमण्लीकरण युग की भारतीय अर्थव्यवस्था में अबुझमाड़िया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था में आर्थिक विकास व भूमण्डलीकरण का प्रभाव (छ.ग. राज्य के जिला- नारायणपुर के विशेष सन्दर्भ में) पर आधारित है। शोध पत्र के तथ्यों का संकलन प्राथमिक स्रोत के साक्षात्कार और अनुसूची पद्धति एवं द्वितीयक स्रोतो में अभिलेखों का सहारा लिया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र जनजातीय समाज पर भारतीय अर्थव्यवस्था और भूमण्डलीकरण के प्रभावों को दर्शाता है।

शोध पत्र

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-01 में कहा गया है कि इण्डिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, संविधान के इस अनुच्छेद के बारे में अक्सर यह चुटकी ली जाती है कि यह भूमण्डलीकृत भारत की सही तस्वीर प्रस्तुत करता है भूमण्डलीकृत भारत एक सम्पूर्ण इकाई में नहीं बल्कि दो अलग-अलग इकाईयों के रूप में देखा जा सकता है। पहली इकाई है- सामान्य भारतीय का; भारत जो विशेषकर गाँवो, कस्बों, छोटे शहरों एवं नगरों में निवास करता है। भारत में यह वर्ग अपने जीवन-यापन के लिए राजसत्ता से कहीं अधिक ईश्वर पर भरोसा करता है। भारतीयों का यह बड़ा वर्ग सामान्यतः गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करता है या फिर गरीब

realme Shot on realme C25s

2020-2021 Entry No. (1)

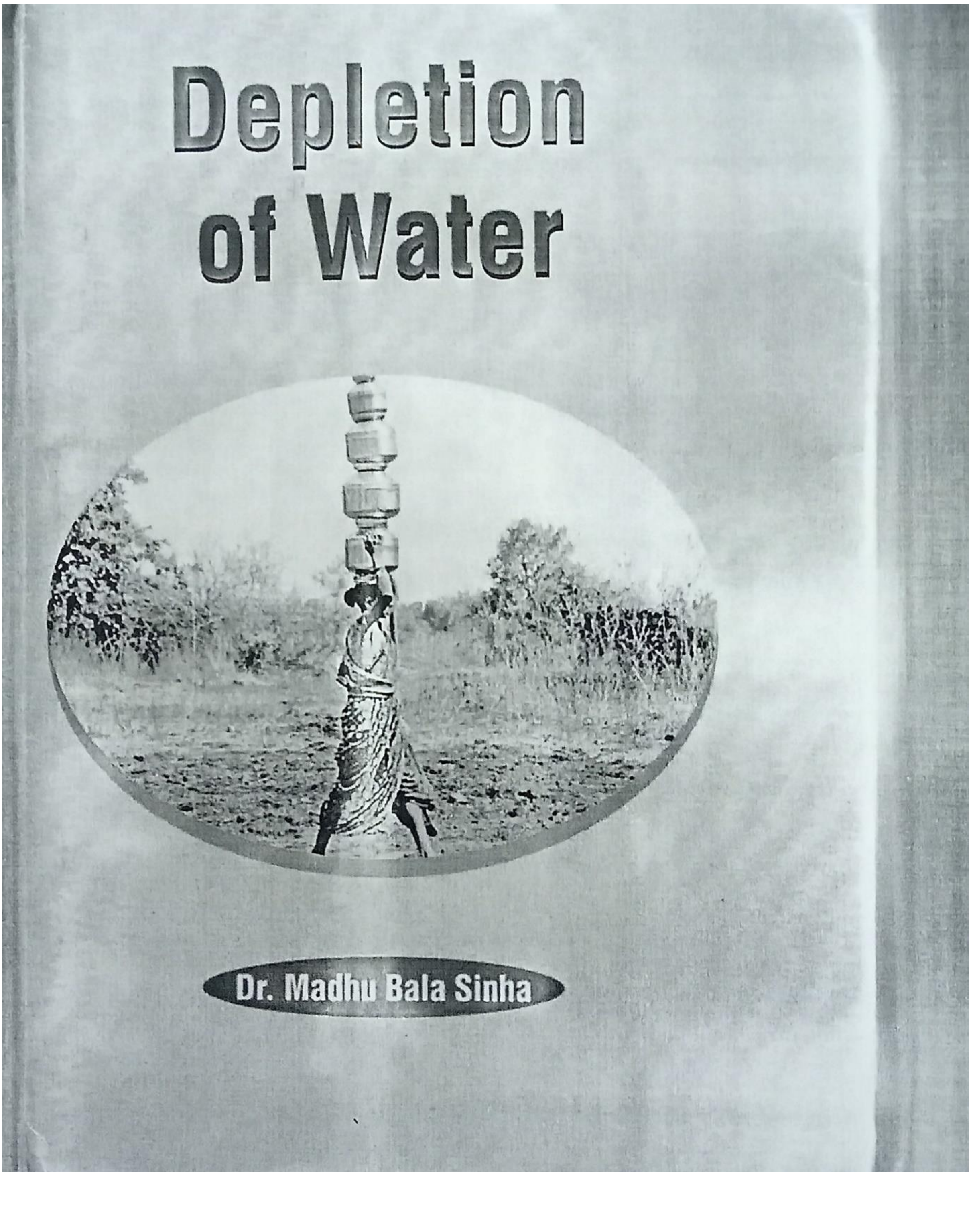

ISBN 978-81-952235-4-1, Depletion of Water, ISDR, Ranchi, India

जल वर्तमान की प्रमुख आवश्यकता

मीनाक्षी ठाकुर
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, बस्तर विश्वविद्यालय, बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत
सम्प्रति: अतिथि सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग,
शासकीय स्वामी आत्मानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नारायणपुर, छत्तीसगढ़, भारत

जल समस्त नैसर्गिक संसाधनों में महत्वपूर्ण है। यह मानव जीवन का मूलाधार है। जल में ही ऐसी शक्ति है जो मानव की भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानसिक आवश्यकताओं को एक साथ पूर्ण कर सकती है। जल की नैसर्गिक गुणवत्ता में कलुषता की विद्यमानता जल प्रदूषण कहलाती है। जीवन का आधार है जल। दैनिक घरेलू क्रियाएँ, औद्योगिक एवं कृषि कार्यों में जल की व्यापक आवश्यकता होती है। आज का युग विज्ञान का युग है। अत: आज के दौर में भौतिक प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना अति आवश्यक हो गया है।

संरक्षण शब्द सम् + रक्षण के संयोग से निर्मित है जिसका आशय है समान रूप में रक्षा करना। देश में जनसंख्या में हुई आशातीत वृद्धि से पानी की कमी हो गई है। कुल वर्षा का 10 प्रतिशत भाग तो देश में ही खत्म कर लिया जाता है। शेष जल पृथ्वी की सतह के नीचे चला जाता है जिसका उपयोग नलकूपों द्वारा पानी बाहर निकालकर कर लिया जाता है। प्रतिवर्ष भारत में करीब 16,900 ट्यूबबेल नये लग जाते हैं जिनकी वजह से पानी का स्तर कम होने लगा है। तालाब तथा झीले सूखने लगी है। अत: आवश्यकता है कि अब जल तथा जलाशयों जैसे प्राकृतिक संसाधनों का समुचित संरक्षण होना चाहिए। तालाब तथा झील बढ़ती जनसंख्या के उपयोग से निरन्तर सूखने लगे हैं, उनमें जल स्तर कम हो जाने पर नीचे गाद इत्यादि जम जाती है। कई बार जलकुम्भी नामक पौधा बड़ी मात्रा में स्वत: उत्पन्न हो जाता है, जो पानी को अधिक सोखता है। अत: ऐसे पौधे तथा खरपतवार इत्यादि को निकालकर झीलो तथा तलाबों की सफाई की जानी चाहिए, ताकि उनमें गहराई करके साफ पानी को अधिक स्टोर किया